वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 03 अगस्त 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अभाविप के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को 17 सूत्रीय माँग पत्र सौंपा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन की रखी माँग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कोरोना काल में छात्रों को हो रही शिक्षा संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और 17 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा।

अपने मांगपत्र में अभाविप ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तुरंत क्रियान्वयन, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति बढ़ाने, कोरोना काल में शिक्षा शुल्क से अतिरिक्त सभी शुल्क की माफ़ी एवं NET उत्तीर्ण छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने जैसी विशेष माँगें मांगपत्र में सम्मिलित की। ई पुस्तकालय और पठन सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ विद्यार्थियों को किश्तों में शुल्क देने की सुविधा प्रदान की जाए आदि माँगों को सम्मिलित किया। कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुये शैक्षणिक संस्थानों को अति-शीघ्र खोलना, तथा उच्च- शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के टीकाकरण की माँग भी रखी गयी।

अभाविप का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वन हेतु यू.जी.सी. को निश्चित दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे समय सीमा के अंदर उच्च-शिक्षण संस्थान NEP के प्रावधानों को लागू कर सकें। शिक्षा जगत में निजी संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी ढंग से शुल्क में वृद्धि करने जैसी अराजकता को रोकने के लिए शुल्क नियंत्रक कानून बनाया जाए, निजी शिक्षा क्षेत्र में हो रहे फ़र्जीवाड़े को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो, भारत केंद्रित पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन तथा स्वावलंबी शिक्षा को देखते हुए कृषि विज्ञान शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में अतिशीघ्र जोड़ा जाए, और अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं, शिक्षा मंत्रालय को सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विभागों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए ताकि छात्रों से संबंधित विषय पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को संविधान सम्मत आरक्षण उपलब्ध कराया जाए, योग एवं आयुर्वेद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए आदि मुख्य सुझावों को सम्मिलित किया है गया है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण जिन समस्याओं से शिक्षा क्षेत्र जूझ रहा है उनके समाधान को प्रतिनिधि मण्डल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा है। शिक्षा मंत्री ने सभी विषयों का संज्ञान लिया एवं जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है।" प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सभी राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक एवं डूसू अध्यक्ष उपस्थित रहे।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)